

प्रेषक,

श्रीमती इन्दिरा आशीष
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 11 मई, 2010

विषय- श्री कुंवर सिंह खत्री, सहायक अधीक्षक, महाधिवक्ता कार्यालय को पद के
अनुरूप उच्चीकृत वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 88/नया0वेत0 संशो/2009 दिनांक 19-11-2009 एवं शासनादेश संख्या- 86/xxxvi(1)/09-237जी0/2001 दिनांक 7 सितम्बर, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाधिवक्ता कार्यालय में कार्यरत श्री कुंवर सिंह खत्री, सहायक अधीक्षक को उनकी सहायक अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के दिनांक 8-6-2009 से लागू वेतनमान रू0 6500-10500 को निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन उच्चीकृत किया जाता है:-

क्रम सं०	पद	वर्तमान वेतनमान	संशोधित वेतनमान	सादृश्य बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1	वाद अधीक्षक/ सहायक अधीक्षक	6500- 10500	7500-12000 8000- 13500 (चार वर्ष पूर्ण करने पर)	वेतन बैण्ड-2 वेतन बैण्ड-3	4800 5400 (चार वर्ष पूर्ण करने पर)

(1) इस वेतनमान का लाभ प्रदान करने से पूर्व महाधिवक्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि श्री कुंवर सिंह खत्री, सहायक अधीक्षक, की नियमानुसार नियमित नियुक्ति/पदोन्नति हुई है और इनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक है और इनके विरुद्ध कोई शिकायत /जांच लम्बित नहीं है। यदि भविष्य में इन्हें इनके मूल विभाग में वापस किया जाता है तो इन्हें वापस जाने पर तत्समय देय वेतनमान अनुमन्य होगा। श्री खत्री एवं उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 7 सितम्बर, 2009 में उल्लिखित कार्मिकों के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्मिक को भविष्य में उक्त लाभ की अनुमन्यता बनने पर उस पदधारक की नियुक्ति सम्बन्धित सेवा नियमावली/राज्य सरकार के विभागों के अधीन नियमानुसार

नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करने तथा उसके समस्त अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने पर न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति से ही उक्तवत वेतनमान अनुमन्य होगा।

(2) सहायक अधीक्षक को उच्चतर वेतनमान मिलने के फलस्वरूप उनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृद्धि अपेक्षित है। अनुस्मारकों, लम्बित पत्रावलियों एवं संदर्भों का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किये जायेगे।

(3) दिन प्रतिदिन कार्यों में प्रयुक्त होने वाले आदेश एवं नियम कम्प्यूटर पर रखे जायेगे ताकि आवश्यकतानुसार पत्रावली पर उनका उद्धरण अंकित किया जा सकें।

(4) नैत्यक किस्म के कार्य सहायक अधीक्षक के स्तर पर ही निबटाये जायेगें।

(5) अनुभाग का Reference Register कम्प्यूटर पर ही रखा जायेगा।

(6) सहायक अधीक्षक द्वारा अपने अनुभाग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा एवं अधीनस्थों के कार्य का मूल्यांकन कर आख्या महाधिवक्ता को प्रस्तुत की जायेगी।

(7) महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक छमाही में अनुभागों का निरीक्षण कर अधीक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा।

2- उक्त अधिकारी को निर्धारित समयावधि एवं औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर नॉन फक्शनल वेतनमान रू0 8000-275-13500 का लाभ प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप उन्हें समयमान वेतनमान की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत आगे लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3- उपरोक्त अनुमन्य कराये गये नॉन फक्शनल वेतनमान से सम्बन्धित सहायक अधीक्षक का वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22 ए(1) के अनुसार किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00- आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहाकार और परामर्शदाता(काउन्सिल)- 03-महाधिवक्ता -00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामों में डाला जायेगा।

भवदीया,

(श्रीमती इन्दिरा आशीष)

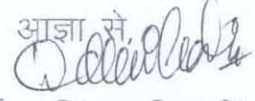
प्रमुख सचिव,

संख्या- 95 /xxxvi(1)/10-23/2009तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस-सी-1/105 इन्दिरा नगर, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारपुर रोड, माजरा, देहरादून।

- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 4- वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- विभागीय आदेश पुस्तिका।
- 6- एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

आज्ञा से


(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव,